



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2009/फाल्गुन 26, 1930

No. 111]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2009/PHALGUNA 26, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के आयातों से संबंधित निर्णायक पाटनरोधी समीक्षा जांच ।

सं. 15/1/2008-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि:

1. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपशीर्ष 2831.10.10 तथा 2832.10.20 के अंतर्गत आने वाले जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 25.2.2003 की अधिसूचना सं. 14/34/2002-डीजीएडी के तहत प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क दिनांक 1 अप्रैल, 2003 की सी.शु. अधिसूचना सं. 61/2003-सी.शु. के तहत लगाया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/34/2002-डीजीएडी द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 को अंतिम जांच परिणाम निकाले थे और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना सं. 173/2003-सी.शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्रीज लि., बड़ोदरा द्वारा इस आशय के अनुरोध और मै. डेमोसा केमिकल्स प्रा.लि., मुंबई तथा मै. टीसीपी लि., चेन्नई द्वारा इस अनुरोध के समर्थन के बाद जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फेट (एचएसएस) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि उपाय समाप्त किए जाने से पाटन और/अथवा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। याचिकाकर्ता ने प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ यह दावा किया था कि इन देशों से संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रहने और उसकी अवधि आगे और 5 वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3. समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार के प्रति संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत तथा इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार दिनांक 19.3.08 की अधिसूचना सं. 15/1/2008-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा शुरू की थी।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :-

- (i) समीक्षा शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर तथा आवश्यक सूचना मांगते हुए घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा ज्ञात आयातकों को अधिसूचित किया ;
- (ii) नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वह निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।
- (iii) संगत सूचना मांगने के लिए जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्राधिकारी ने प्रश्नावलियां भेजीं।

➤ बीएसएसएफ एक्टिंगेसेसाफ्ट-जर्मनी

➤ मै. हंसोल केमिकल-कोरिया

तथापि, इनमें से किसी निर्यातक ने उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है।

- (iv) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2006 से 30 सितम्बर, 2007 (18 माह) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वित्त वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 और जांच अवधि शामिल थी।
- (v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के घोर प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। डीजीसीआईएंडएस से अनुरोध की गई सूचना प्राप्त हो गई है।
- (vi) संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने क्षति अवधि हेतु लागत तथा क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है।
- मै. ट्रान्सपैक-सिलोक्स इंडस्ट्री लि.
 - मै. टीसीपी लि.
 - मै. डेमोसा केमिकल्स प्रा. लि.
- (vii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली के साथ जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भी भेजी गई थी।
- | | |
|--|--|
| ➤ मालवा इंडस्ट्रीज लि. | ➤ मॉडर्न डेनिम |
| ➤ ओसवाल डेनिम | ➤ एस.कुमार्स लि. |
| ➤ गिनी इंटरनेशनल, | ➤ आर्किड केमिकल्स एंड फार्मा. लि. |
| ➤ द अरविन्द मिल्स लि. | ➤ मदुरा कोट्स लि. |
| ➤ भिवानी टेक्सटाइल्स मिल्स | ➤ जीएसआई(इंडिया) लि. (पूर्ववर्ती गुज. स्पिनर्स लि.) |
| ➤ सिस्सि इंडिया लि. | ➤ ग्यानचंदरामजी दास |
| ➤ मफतलाल बर्लिंगटन इंड. लि. | ➤ रेमंड डेनिम लि. |
| ➤ ब्लू बर्लेइस इंडिया लि. | ➤ रिलायंस टेक्सटाइल्स इंड लि. |
| ➤ के.जी.डेनिम लि. | ➤ बिड़ला वीएक्सएल लि. |
| ➤ श्री रेनुगा साफ्ट-X टावल्स (श्री रेनुगा टेक्सटाइल्स लि. का 100% ईओयू प्रभाग) | ➤ वेल्सपन टेरीटावल्स (वेल्सपन इंडिया लि. की एक इकाई) |
| ➤ सेंच्युरी डेनिम (सेंच्युरी टेक्सटाइल्स एंड इंड लि. का एक प्रभाग) | ➤ रेमंड लि. |
| ➤ जेसीटी लि. | ➤ आंध्रप्रदेश पेपर मिल्स लि. |
| ➤ सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंड | |
| ➤ मोरारजी ब्रेमब्राना लि. | |

तथापि, किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

- (viii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए समस्त विचारों और अनुरोधों पर वर्तमान जांच के लिए संगत सीमा तक विचार किया है।

- (ix) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखा ।
- (x) प्राधिकारी ने हुई क्षति की जांच करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का संभव सीमा तक सत्यापन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।
- (xi) नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 12 जनवरी, 2009 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए समस्त हितबद्ध पार्टियों को अवसर भी प्रदान किया । जिन पार्टियों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था ।
- (xii) हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने जहां अपेक्षित हुआ, वहां गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पार्टियों के समक्ष नहीं किया गया है । जहां कहीं संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टियों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।
- (xiii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पार्टी ने सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा उसने जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।
- (xiv) प्राधिकारी ने आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए हितबद्ध पार्टियों को अनुरोध करने हेतु दिनांक 9.3.2009 को एक विस्तृत प्रकटन विवरण जारी किया और उस पर व्यक्त विचारों को वर्तमान जांच परिणाम में विधिवत शामिल किया गया है ।
- (xv) *** यह चिन्ह इस जांच परिणाम में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने उसे नियमानुसार गोपनीय ही माना है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:

- (i) चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है । इस अवधि में उत्पाद में कोई खास विकास नहीं हुआ है ।
- (ii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है ।

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

6. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टी ने विद्याराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में कोई टिप्पण या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विद्याराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है। विद्याराधीन उत्पाद को कई वैकल्पिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें हाइड्रोसल्फाइड सांद्रण अथवा सोडियम डाइथियोसल्फेट शामिल हैं।

8. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एक रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ है। यह सफेद या भूरे रंग का रवादार पाउडर होता है जो दृष्टव्य विजातीय तत्वों से मुक्त और तेज गंध वाला होता है। इसका आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के उपशीर्ष 2832.10.20. के अंतर्गत किया गया है। यद्यपि उपशीर्ष 2831.10.10 तथा 2832.10.20 से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के वर्णन का पता चलता है परंतु सही सीमाशुल्क वर्गीकरण को सोडियम सल्फाइड्स के रूप में 6 अंकीय शीर्ष 2831.10 के अंतर्गत माना जा सकता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच से सभी प्रकार का सोडियम हाइड्रोसल्फाइड विद्याराधीन उत्पाद के दायरे में आता है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड में कोई खास अंतर नहीं है। जिसका कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा जर्मनी एवं कोरिया गणराज्य से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्राद्योगिकी कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत वितरण एवं विपणन तथा वस्तु टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का अदल-बदल कर उपयोग किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य से आयातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग का आधार एवं क्षेत्र

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

10. (i) यह याचिका मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्री लि. द्वारा दायर की गई थी। भारत में ऐसी 4 कंपनियां हैं जिन्होंने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के उत्पादन की क्षमता सृजित की है अर्थात् मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्री लि., डेमोसा केमिकल प्रा.लि., टीसीपी लि. और गुलशन केमिकल्स लि.। मै. टीसीपी लि. तथा मै. डेमोसा केमिकल्स प्रा.लि. ने याचिका का समर्थन किया है और उन्हें नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जाना चाहिए।

(ii) याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जाना चाहिए।

घ.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

11. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टी ने "घरेलू उद्योग" के बारे में कोई टिप्पण या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

घ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. भारत में संबद्ध वस्तु के 4 उत्पादक हैं अर्थात् मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्री लि., डेमोसा केमिकल प्रा.लि., टीसीपी लि. और गुलशन कैमिकल्स लि.। पाटनरोधी शुल्क मी समीक्षा, उसे जारी रखने तथा उसमें वृद्धि करने हेतु याचिका ट्रांसपैक्स सिलोक्स इंडस्ट्री लि. द्वारा दायर की गई थी और इसका मै. डेमोसा केमिकल प्रा.लि. तथा टीसीपी लि. ने समर्थन किया था। जांच शुरुआत के बाद टीसीपी लि. तथा डेमोसा केमिकल प्रा.लि. ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराई है। ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्री लि., डेमोसा केमिकल प्रा.लि. और टीसीपी लि. का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% के हिस्से से भी अधिक बनता है।

13. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित, पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में (ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा)।"

14. इस प्रकार ऐसी किसी स्थिति में जब समग्र घरेलू उत्पादकों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो प्राधिकारी के लिए नियमों के तहत उन उत्पादकों पर विचार करना अपेक्षित होता है जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो। अतः विधिक उपबंधों तथा वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियमों के अर्थ के भीतर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्री लि., डेमोसा केमिकल प्रा.लि. और टीसीपी लि. घरेलू उद्योग है।

ड. पाटन का निर्धारण

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

15. (i) जर्मनी में सामान्य मूल्य का निर्धारण यूरोपीय समुदाय (ईसी) में प्रचलित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य का दावा ईसी में वास्तविक बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। निर्यात कीमत का दावा आयात कीमत के भारित औसत के आधार पर किया गया है। सीआईएफ आयात कीमत और कारखाना स्तर के बीच किए गए व्यय पर विचार करते हुए यह देखा जाएगा कि विदेशी उत्पादकों ने पाटन जारी रखा है।

- (ii) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में यूरोप से पाटन जारी रहने की संभावना है। यूरोप में घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं होने के कारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में और वृद्धि होने की संभावना है।

ड.2 निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

16. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टी ने सामान्य मूल्य के बारे में कोई टिप्पण या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. धारा 9 (1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) सामान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

जर्मनी

सामान्य मूल्य

18. जर्मनी के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र तथा ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने उस कीमत का साक्ष्य उपलब्ध कराया है जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री ईयूके घरेलू बाजार में की गई है। किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने ऐसी कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिसका उपयोग सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जा सके। निर्धारित प्रपत्र में सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने सार्वजनिक क्षेत्र (वर्ल्ड ट्रेड एटलस) से आंकड़े एकत्र प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु संबद्ध के लिए कोई विशिष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त ईयू

में बिक्री कीमत के संबंध में सूचना पर भी भरोसा किया । तदनुसार कारखाना स्तर पर सामान्य मूल्य निम्नानुसार *** अम.डॉ. प्रति मी.टन निकाला गया है :

कीमत यूरो/मी.ट. में	बीजक 1	बीजक 2	औसत
मात्रा (किग्रा.)	***	***	***
मूल्य (यूरो)	***	***	***
सीआईएफ कीमत (यूरो/मी.ट.)	***	***	***
स्थानीय भाड़ा तथा बीमा (अनुमानित)	***	***	***
30/60 दिन के ऋण की दर से ऋण लागत	***	***	***
ईसी में प्रचलित कीमत	***	***	***
परिवर्तन दर : यूरो से अम.डॉ. में	***	***	***
ईसी में प्रचलित कीमत अम.डॉ. में	***	***	***

निर्यात कीमत

19. जर्मनी के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र तथा ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । घरेलू उद्योग ने उस कीमत का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जिस कीमत पर जांच अवधि में वस्तु का आयात किया गया था । किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने ऐसी कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिसका उपयोग निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए किया जा सके । निर्धारित प्रपत्र में सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया । तदनुसार जर्मनी से आयात हेतु डीजीसीआईएंडएस द्वारा सूचित आंकड़ों पर भारित औसत आयात कीमत के निर्धारण हेतु भरोसा किया गया है । चूंकि यह कीमत सीआईएफ स्तर पर है, इसलिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय तथा बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके । कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निम्नानुसार *** अम.डॉ. प्रति मी.टन निकाली गयी है :

विवरण	इकाई	कीमत/मी.ट.
निर्यात कीमत सीआईएफ	रू./मी.ट.	41,493
परिवर्तन दर	1 अम.डॉ.	44.27
निर्यात कीमत सीआईएफ	अम.डॉ./मी.ट.	937.27
समुद्री भाड़ा	अम.डॉ./मी.ट.	***

समुद्री बीमा 0.5%	अम.डॉ./मी.ट.	***
एफओबी निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***
अंतरदेशीय भाड़ा - 1%	अम.डॉ./मी.ट.	***
पत्तन व्यय - 0.5%	अम.डॉ./मी.ट.	***
बैंक प्रभार - 0.5%	अम.डॉ./मी.ट.	***
निवल निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***

पाटन मार्जिन

20. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद जांच अवधि के दौरान भारत में सूचित आयातों के बारे में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। पाटन मार्जिन *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार परिकलित निर्यात कीमत का ***% बनता है।

विवरण	इकाई	कीमत/मी.ट.
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	***
निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन %	%	50-60%

कोरिया आरपी

कोरिया आरपी में सामान्य मूल्य

21. कोरिया गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र तथा ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। किसी उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उत्पादन लागत का अनुमान लगाकर उसके परिकलन के आधार पर कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया। कोरिया गणराज्य हेतु इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है। अतः किटा-ऑर्ग से लेकर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रमुख कच्ची सामग्री (मेथानोल तथा सोडा लाई) की आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है। जो भारत में कच्ची सामग्री के आयात के बारे में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य से अधिक है। सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों का भारत औसत, प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् सोडियम फॉर्मेट, मेथानोल एवं कार्बोस्टिक सोडा की कीमत, इन कच्ची

सामग्रियों के लिए सर्वोत्तम खपत कारक और सगत अवधि के दौरान परिवर्तन लागत के सर्वोत्तम ज्ञात अनुमानों को अपनाकर किया गया है। बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत और उचित लाभ मार्जिन को इस प्रकार निर्धारित उत्पादन लागत में जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य की गणना निम्नानुसार की गई है :

	रुपए प्रति मी.ट.
कच्ची सामग्री लागत	***
उपयोगिताएं	***
परिवर्तन लागत	***
वित्तीय लागत	***
संपूर्ण उत्पादन लागत	***
उचित लाभ 5% की दर से	***
सीएनवी प्रति मी.ट.	***
परिवर्तन दर	***
सीएनवी अम.डॉ. प्रति मी.ट.	***

निर्यात कीमत

22. यद्यपि वैबसाइट www.kita.org में उपलब्ध सूचना के आधार पर कोरिया गणराज्य से भारत में इस समय कोई आयात नहीं हुआ है। तथापि, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि कोरिया गणराज्य से कई अन्य देशों अर्थात् वियतनाम, इंडोनेशिया, बंगलादेश और पाकिस्तान आदि को एफओबी आधार पर *** अम.डॉ. की दर से अत्यधिक निर्यात हुए हैं। समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए स्वीकार्य समायोजन करने के बाद तीसरे देश के संबंध में कोरिया गणराज्य के बारे में प्राधिकारी ने कारखाना निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. के रूप में किया है :

विवरण	इकाई	कीमत/मी.ट.
एफओबी निर्यात कीमत (कोरिया से विश्व के लिए)	अम.डॉ./मी.ट.	***
अंतरदेशी भाड़ा - 1%	अम.डॉ./मी.ट.	***
पत्तन व्यय - 0.5%	अम.डॉ./मी.ट.	***
बैंक प्रभार - 0.50%	अम.डॉ./मी.ट.	***
निवल निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***
परिवर्तन दर	44.27	

पाटन मार्जिन

23. प्राधिकारी ने यह नोट किया कोरिया गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और कोरिया गणराज्य से कई देशों को हुए पर्याप्त निर्यातों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने तीसरे देशों को हुए इन निर्यातों के संबंध में पाटन की मात्रा निर्धारित की है। सामान्य मूल्य और उस कीमत के अनुमान पर विचार करते हुए जिस कीमत पर वस्तु का निर्यात विभिन्न देशों को किया गया है, अन्य देशों को हुए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ तीसरे देशों के लिए भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया था। यह पाया गया था कि तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. है जो निर्यात कीमत का ***% बनता है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इस बात की प्रबल संभावना है कि कोरिया गणराज्य द्वारा उस कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा सकता है जिस कीमत पर वह तीसरे देशों को निर्यात कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इससे पाटन की पुनरावृत्ति हो सकती है। कोरिया गणराज्य के संबंध में पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है:

विवरण	इकाई	कीमत/मी.ट.
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	***
निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन %	%	20-30%

उ.4 पाटन की संभावना**जर्मनी****घरेलू उद्योग के विचार**

- 24 (i). पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी निर्यातकों ने अत्यधिक पाटन जारी रखा है। इस प्रकार यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने में सफल रहे हैं (वस्तुतः मात्रा में अधिक वृद्धि हुई है)। यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान पाटनरोधी समाप्त किए जाने की स्थिति में मात्रा में ही वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में पर्याप्त रूप में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। मूल जांच और वर्तमान में मापदंडों/परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटन जारी रहा है और पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा :-

देश	मूल जांच	वर्तमान जांच
<u>जर्मनी</u>		50-60%
➤ बीएसएफ	22.97%	
➤ अन्य	35.55%	
<u>कोरिया</u>	98.01%	लगातार कोई निर्यात नहीं

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक और पर्याप्त है अपितु पाटन मार्जिन की मात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है ।

- (ii) जर्मनी में उत्पादकों ने पर्याप्त उच्च क्षमताएं सृजित की हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

कंपनी	क्षमता (टीपीए)
बीएसएफ	***
बीएसएफ	***
ब्रगमेन	***

- (iii) जर्मनी द्वारा जिस कीमत पर सामग्री का भारत को निर्यात किया जा रहा है वह पाटन जारी रहने का एक संकेतक भी है । पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क के बिना) पर कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है । इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय कीमतें अत्यधिक मात्रा में निर्यात करने के लिए विदेशी उत्पादकों हेतु और अधिक आकर्षक बन जाएंगी । यदि भारत में पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा तो ये उत्पादक बेहतर कीमत हासिल करने के लिए ये मात्राएं भारतीय बाजार में भेज देंगे । अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहेगी ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

25. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने या उसकी मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित सूचना/साक्ष्य पर विचार किया था :

- (i) शुल्क लागू किए जाने के बाद भी जर्मनी से संबद्ध वस्तु का आयात अत्यधिक कम और पाटित कीमतों पर जारी रहा है। मूल जांच और वर्तमान जांच के समय प्रचलित मापदंडों/परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में जर्मनी के उत्पादकों द्वारा उत्पाद का पाटन जारी रखने की संभावना है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :

	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि
आयातों की प्रारंभ कीमत				
संबद्ध देश	41576	41684	49882	46099
अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	36712	30329	26288	42244
निवल बिक्री प्राप्ति (रु./मी.ट.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100.00	92.74	99.95	104.38
अतिरिक्त कीमत				***

- (ii) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि जर्मनी के उत्पादकों ने निम्नानुसार काफी अधिक मात्राएं सृजित की हैं। :

कंपनी	क्षमता (टीपीए)
बीएसएफ	***
बीएसएफ	***
ब्रगमैन	***

यद्यपि, घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त दावे के समर्थन में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और उपर्युक्त के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और चूंकि निर्यातक उपर्युक्त दावे का खंडन करने के लिए आगे नहीं आए हैं। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि जर्मनी में मुक्त रूप से निपटाने योग्य क्षमताएं हैं।

कोरिया गणराज्य

घरेलू उद्योग के विचार :

26. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं:

- (i) चूंकि कोरिया से कोई आयात नहीं हुआ है, इसलिए प्राधिकारी के लिए पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित है ।
- (ii) कोरिया गणराज्य द्वारा चीन से अत्यंत कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है । अतः शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होगी ।
- (iii) कोरिया द्वारा जिस कीमत पर तीसरे देशों को उत्पाद का निर्यात किया जा रहा है वह संबंधित सामान्य मूल्य से काफी कम है जिससे तीसरे देश को हुए निर्यातों के पाटन की पुष्टि होती है ।
- (iv) कोरिया द्वारा जिस कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है वह भारत में प्रचलित कीमत से काफी कम है । अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में कोरियाई उत्पादक तीसरे देश से अधिक कीमत पर सामग्री का निर्यात करने की स्थिति में आ जाएंगे और तब भी वह भारत में प्रचलित कीमत से काफी कम होगी ।
- (v) कोरिया के निर्यातकों द्वारा भारत में अत्यधिक कीमत कटौती हो रही है और अब भी कोरियाई आपूर्तियों को तीसरे देशों में प्राप्त की जा रही कीमतों से अधिक कीमत मिल रही है । इससे पाटन एवं क्षति की संभावना की स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. www.kita.org में कोरिया गणराज्य के प्रकाशित आंकड़ों से उनके देश में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के पर्याप्त आयात जारी रहने का पता चलता है । इनमें से अधिकांश आयात (लगभग 99%) चीन से हुए हैं जो एक ऐसा देश है जिस पर भारत में पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है । इसके अलावा, कोरिया गणराज्य से निर्यात की कीमत जो अनुमानित सामान्य मूल्य से कम है, वह कोरिया में आयात कीमत से काफी अधिक है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा:

	मात्रा (मी.ट.)	अम.डॉ. प्रति मी.ट.
परिकल्पित सामान्य मूल्य		***
विश्व भर से कोरिया में आयात	7946.08	671.78
चीन से कोरिया में आयात	7867.65	663.48
कोरिया की निर्यात कीमत		867.82

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर कोरिया गणराज्य के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने/उसमें कमी किए जाने की स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि कोरिया गणराज्य भारत में पाटन पुनः शुरू कर सकता है । यद्यपि चीन के खिलाफ वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के कारण चीन के मूल की संबद्ध वस्तु भारत में सीधे कोरिया गणराज्य के जरिए सुरक्षित रास्ता प्राप्त नहीं कर सकती है तथापि, इससे कोरिया गणराज्य में उत्पादक बेशी क्षमता तैयार हो सकती है जिसका भारत में पाटन किया जा सकता है । इसके अलावा, भारत में बिक्री कीमत ***रुपए./मी.ट. (***) अम.डॉ./मी.ट.) के रूप में विचार करते हुए कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु की कम आयात कीमत और भारत में संबद्ध वस्तु की उच्च कीमत/मांग

भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन करने के लिए कोरियायी उत्पादकों/निर्यातकों हेतु अधिक आकर्षक हो सकती है।

च. क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण

च.1 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

28. जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

29. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में कई तर्क दिए हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है। मुख्य तर्क ये हैं कि

- (i) घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2004-05 में भारी गिरावट आई और तत्पश्चात वर्ष 2005-06 में सुधार हुआ। तथापि, निष्पादन में प्रस्तावित जांच अवधि में पुनः गिरावट आई है।
- (ii) लाभ, क्षमता उपयोग जैसे मापदंडों से क्षति अवधि के दौरान गिरावट का पता चलता है।
- (iii) नकद लाभ एवं निवेश पर आय जैसे मापदंड नकारात्मक बने रहे।
- (iv) बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री मात्रा जैसे मापदंड इष्टतम से कम रहे।
- (v) घरेलू उद्योग द्वारा पाटित आयातों के न होने पर और अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती थी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन, उत्पादकता तथा अन्य संबंधित मापदंडों में सुधार हो सकता था।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से वर्तमान पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के पाटन और उसके कारण हुई क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच शुरू करने से पूर्व घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही शुरू करते हैं।

31. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के अनुवर्ती प्रभाव की वस्तुपरक जांच किए जाने का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या आयातों में सापेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से अत्यधिक कीमत कटौती हुई है,

अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक हास या कीमत में वृद्धि जो कि अथवा काफी अधिक होती, को रोकने के रूप में हुआ है ।

32. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

33. प्राधिकारी ने क्षति की जांच के बारे में दिए गए तर्कों को नोट किया है और उठाए गए मुद्दों पर उचित स्थानों पर विचार किया है । हितबद्ध पार्टियों के तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति संबंधी मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

34. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों तथा कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की संचयी जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन तथा क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की जा सके । तदनुसार पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है :

क) मांग का निर्धारण

35. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/मांग के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा है जिसका संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है :

इकाई मी. टन में	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि वार्षिक
घरेलू उद्योग की बिक्री	23412	24015	25716	25971
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	7500	7500	9022	8397
कुल आयात	1518	1365	987	3888
मांग	32430	32880	35725	38256

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और इसमें क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में लगभग 18% की वृद्धि हुई है।

ख) आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

36. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है।"

37. प्राधिकारी ने फरवरी, 2007 तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और तत्पश्चात आईबीआईएस के आंकड़ों के अनुसार तथा डीजीसीआईएंडएस स्रोत से सौदेवार आयात आंकड़ों के साथ उनकी तुलना करने के बाद घरेलू उद्योग के दावे की जांच की है और यह पाया गया है कि इसमें कोई खास अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने केवल डीजीसीआईएंडएस स्रोत के आधार पर ही आयातों की मात्रा का निर्धारण किया है।

	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि वार्षिक
आयात (मी.ट.)				
➤ जर्मनी से	335	156	338	1423
➤ कोरिया से	36	67	0	0
➤ संबद्ध देश	371	223	338	1423
➤ अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	517	765	545	1937
➤ अन्य देश	630	378	103	528
➤ कुल आयात	1518	1366	986	3888
आयातों में बाजार हिस्सा (%)				
➤ जर्मनी	22.07	11.42	34.28	36.60
➤ कोरिया गणराज्य	2.37	4.91	0.00	0.00
➤ संबद्ध देश	24.44	16.33	34.28	36.60

➤ अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	34.06	56.00	55.27	49.82
➤ अन्य देश	41.50	27.68	10.45	13.58
मांग (मी.ट.)	32430	32880	35725	38256
मांग में बाजार हिस्सा (%)				
➤ जर्मनी	1.03	0.47	0.95	3.72
➤ कोरिया गणराज्य	0.11	0.21	0.00	0.00
➤ संबद्ध देश	1.14	0.68	0.95	3.72
➤ अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	1.60	2.33	1.53	5.06
➤ अन्य देश	1.94	1.15	0.29	1.38
➤ घरेलू उद्योग	72.19	73.04	71.98	67.89
➤ अन्य उत्पादक	23.13	22.81	25.25	21.95
➤ भारतीय उद्योग	95.32	95.85	97.23	89.84
भारतीय उद्योग का उत्पादन (मी.ट.)	32288	34578	36172	35626
भारतीय उद्योग के उत्पादन की तुलना में पाटित आयात (%)				
➤ जर्मनी	1.04	0.45	0.93	4.00
➤ कोरिया गणराज्य	0.11	0.19	0.00	0.00
➤ संबद्ध देश	1.15	0.64	0.93	4.00
➤ अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	1.60	2.21	1.51	5.44

प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

- संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा 2003-04 तथा 2005-06 के बीच स्थिर रही है । तथापि, जांच अवधि में इसमें तेजी से वृद्धि हुई है ।
- क्षति अवधि और खासकर जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- संबद्ध आयातों के संबंध में मांग में बाजार हिस्सा जो वर्ष 2003-04 के दौरान 1.14% था वह जांच अवधि में 3.72% के स्तर पर पहुंच गया । इसी समय जिन अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू था, उनके हिस्से में भी इस अवधि में वृद्धि हुई है । परिणामतः घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2003-04 में 72.19% था, जांच अवधि में घटकर 67.89% हो गया ।

- iv) भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से हुए आयात में वर्ष 2003-04 तक गिरविट आई और तत्पश्चात वर्ष 2003-04 में 1.15% की तुलना में जांच अवधि में बढ़कर यह 4% के स्तर पर पहुंच गया ।
- v) संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है ।

ग) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

38. किसी समीक्षा जांच में इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत प्रभाव पड़ा है अथवा क्या शुल्क समाप्त किए जाने के बाद कीमत प्रभाव की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

39. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक हास या कीमत में वृद्धि जो कि अथवा काफी अधिक होती, को रोकने के रूप में हुआ है । घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत का विश्लेषण किया गया है जिससे निम्नानुसार पता चलता है:

सीआईएफ निर्यात कीमत रु./मी.ट.	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि वार्षिक
संबद्ध देशों से आयात	32931	34392	42946	41493
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	29079	25024	22633	38023
समस्त आयात	28871	26206	29690	37105
निवल बिक्री प्राप्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100.00	92.74	99.95	104.38

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमत में उतार-चढ़ाव भारत में आयात कीमत के अनुरूप हुआ है । यह भी नोट किया जाता है कि जिन अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है और संबद्ध देशों के बीच कीमत अंतर वर्ष 2004-05 और 2005-06 के बीच काफी अधिक रहा था जिससे संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा कम रही है । तथापि, जांच अवधि में कीमत अंतर कम होने के कारण संबद्ध आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

घ) कीमत कटौती

41. पाटित आयातों द्वारा की जा रही कीमत कटौती का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति की गणना रिबेट और करों को घटाने के बाद की गई थी। आयातों के पहुंच मूल्य की गणना संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य में 1% हैंडलिंग प्रभाव और लागू मूल सीमाशुल्क को जोड़कर की गई है। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई थी और यह पाया गया था कि पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की जा रही है। ऐसा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :

	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि
सीआईएफ निर्यात कीमत रु./मी.ट.				
संबद्ध देश	32931	34392	42946	41493
अन्य देश जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है	29079	25024	22633	38023
सीमाशुल्क	25%	20%	15%	10%
आयातों की पहुंच कीमत				
संबद्ध देश	41576	41684	49882	46099
अन्य देश जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है	36712	30329	26288	42244
निवल बिक्री प्राप्ति (रु./मी.ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	92.74	99.95	104.38
बिक्री की लागत (रु./मी.ट.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	102.62	97.05	102.94
कीमत कटौती रु./मी.ट.				
संबद्ध देशों से निर्यात	***	***	***	***
अन्य देश जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)				
संबद्ध देशों से आयात	1-10	Negative	Negative	1-5
अन्य देश जहां पाटनरोधी शुल्क लागू है	10-20	20-30	40-50	10-15
सतिरहित कीमत रु./मी.ट.				***

42. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की जा रही थी। इस प्रकार यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आयातों द्वारा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त कटौती की जाएगी। यह भी नोट किया जाता है कि ऐसे अन्य देशों से क्रीम कटौती अत्यधिक सकारात्मक रही है जिन पर इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है। घरेलू उद्योग ने इन शुल्कों में उर्ध्वगामी संशोधन का अनुरोध किया था और प्राधिकारी द्वारा इस समय इन देशों से आयातों के बारे में मध्यावधि समीक्षा जांच की जा रही है।

ड) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

43. इस आशय का निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास/न्यूनीकरण किया जा रहा था, प्राधिकारी ने बिक्री कीमत और उत्पादन लागत में प्रवृत्तियों की तुलना की है जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में भारी गिरावट आई है। तत्पश्चात जहां उत्पादन लागत में गिरावट आई वहीं वर्ष 2005-06 में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। तथापि, जांच अवधि में जब संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, तब बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम रही थी। इस प्रकार आयातों द्वारा जब भी पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की कीमत का न्यूनीकरण हुआ।

घ) घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

44. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों का तथ्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।"

उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग

45. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग में निम्नानुसार उतार-चढ़ाव आयात है।

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि वार्षिक
क्षमता	मी.ट.	31000	31000	32625	37500
उत्पादन	मी.ट.	25169	26371	27152	27361
घरेलू बिक्री	मी.ट.	23412	24015	25716	25971
क्षमता उपयोग	%	81	85	83	73
अप्रयुक्त क्षमता	मी.ट.	5831	4629	5473	10139

यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है किंतु इस अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद अपनी मात्रा को बढ़ाने में समर्थ रहा है। तथापि, यह देखा गया है कि आयात मात्रा में वृद्धि होने के बाद वह उत्पादन और बिक्री में आगे और वृद्धि नहीं कर सका। परिणामतः घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई और उसके पास जांच अवधि में 27% की अप्रयुक्त क्षमता बनी रही।

लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह

46. घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2004-05 तक गिरावट आई और तत्पश्चात आयात की मात्रा में गिरावट आने के कारण वर्ष 2005-06 में सुधार हुआ। तथापि, आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जांच अवधि में लाभप्रदता में पुनः गिरावट आ गई। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100.00	-1,651.75	357.34	123.08
लाभ/(हानि) (पीबीटी)	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100.00	-1,777.40	415.06	144.32
लाभ/(हानि) (पीबीटी)	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	-683.44	327.31	232.61
लगाई गई पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	-702.34	259.65	173.10
नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	-1,740.11	788.99	687.02
आयातों की मात्रा					
➤ संबद्ध देश	मी.ट.	371	223	338	1423
➤ कुल आयात	मी.ट.	1518	1366	986	3888

47. घरेलू उद्योग को वर्ष 2003-04 में कम आय प्राप्त हुई जो वर्ष 2004-05 में नकारात्मक बन गई। घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2006-07 में निवेशों पर अपनी आय में पर्याप्त सुधार किया जा सका। तथापि, आयातों में एक बार फिर वृद्धि होने के कारण जांच अवधि में लाभ में गिरावट आने के कारण जांच अवधि में लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई। निवेश पर आय हर समय उचित स्तर से पर्याप्ततः कम रही थी।

48. समस्त घरेलू उत्पादक बहु उत्पाद कंपनियां हैं और कंपनी के नकद प्रवाह की स्थिति संबद्ध उत्पाद में स्थितियों का संकेतक नहीं होंगी। इस प्रकार प्राधिकारी ने इन वर्षों के दौरान नकद लाभ की जांच की है और जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। जहां तक नकद प्रवाह की स्थिति का संबंध है, उसमें लाभ और निवेश पर आय के समान प्रवृत्ति का पता चलता है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2003-04 में कम नकद प्रवाह हासिल हुआ था जो वर्ष 2004-05 में नकारात्मक बन गया। घरेलू उद्योग अपने नकद लाभ में वर्ष 2006-07 में पर्याप्त सुधार कर सकता था। तथापि, आयातों में पुनः वृद्धि होने के कारण जांच अवधि में लाभ में गिरावट आने से जांच अवधि में नकद लाभ में गिरावट आई।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

49. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	100.19	102.46	103.60
मजदूरी	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सू. बद्ध	100.00	99.74	103.22	116.98
उत्पादकता	मी.ट./व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.57	105.29	105.03

प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। मजदूरी में सामान्य वृद्धि का पता चलता है। प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में उत्पादन में कुछ सुधार प्रदर्शित हुआ है।

मालसूची

50. घरेलू उद्योग के पास तैयार उत्पादों के औसत स्टॉक में निम्नलिखित तालिका के अनुसार गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई :

	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	1733	1549	1219	1003
स्टॉक में बिक्री दिवसों की संख्या	मी.ट.	27	24	17	14

वृद्धि

51. क्षति संबंधी अनेक मापदंडों से जांचाधीन अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रवृत्ति का पता चलता है । जहां वर्ष 2005-06 में पर्याप्त सुधार और सकारात्मक वृद्धि हुई थी वहीं उसमें अनेक मापदंडों के संबंध में नकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई । यद्यपि, उत्पादन, बिक्री मात्रा और मालसूची के संबंध में यह सकारात्मक रही थी ।

ज. अंतिम जांच परिणाम:

52. हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों के जरिए अथवा उपर्युक्त जांच परिणाम में अन्यथा दर्ज की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं क्षति की वर्तमान स्थिति तथा पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और जर्मनी से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन काफी अधिक एवं न्यूनतम सीमा से ज्यादा है ।
- संबद्ध वस्तु के भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आने की संभावना है और कोरिया गणराज्य से आयातों के संबंध में संभावित पाटन मार्जिन काफी अधिक और न्यूनतम सीमा से ज्यादा है ।
- वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है ।
- यद्यपि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में अपने निष्पादन में मामूली सुधार किया है, तथापि जांच अवधि के दौरान उसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है । जर्मनी से हुए पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति पहुंचाई जा रही है तथा कोरिया गणराज्य से पाटन की संभावना घरेलू उद्योग के लिए बनी हुई है जिससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पर्याप्त क्षति होने का खतरा बन गया है । यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया

जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की संभावना है ।

झ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

53. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं । तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की पद्धति द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रूकेंगे और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध वस्तु से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी । उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो से भी अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे ।

54. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो देश के सामान्य हित में है, बहाल की जा सके । पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं हेतु उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ञ. सिफारिशें

55. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य से आयातों के पाटन और उनके कारण होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी की राय यह है कि संबद्ध देशों से आयातों के बारे में इस उपाय की अवधि को बढ़ाना अपेक्षित है ।

56. लागू मौजूदा उपाय को समाप्त किए जाने की स्थिति में वर्तमान पाटन और आसन्नवर्ती पाटन की संभावना की जांच करने के बाद प्राधिकारी उसके द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1, दिनांक 22.10.2003 में प्रकाशित तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3.12.2003 की अधिसूचना सं. 173/2003-सी.शु. के तहत अधिसूचित दिनांक 20.10.2003 के अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं. 14/34/2002-डीजीएडी के तहत संस्तुत पाटनरोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की सिफारिश करते हैं ।

57. इस सिफारिश से केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ उत्पन्न हो सकने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2009

Final Findings

Subject : Sunste Anti-dumping review investigations in the matter relating to imports of Sodium Hydrosulphite originating in or exported from Germany and Korea RP.

No. 15/1/2008-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A Background of the Case

1. The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Sodium Hydrosulphite (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Germany and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries) falling under Sub-heading 2831.10.10 and 2832.10.20. The preliminary findings were published vide Notification No 14/34/2002-DGAD dated 25/2/2003 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 61/2003-Customs dated 1st April 2003. The Designated Authority came out with final findings on 20th October 2003 vide Notification No 14/34/2002-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Ministry of Finance as per Notification No. 173/2003-Customs dated 3rd December 2003.

2. The Designated Authority initiated the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Sodium Hydrosulphite (SHS) originating in or exported from Germany and Korea RP following a request to this effect by the

Domestic Industry M/s Transpek Silox Industry Ltd., Vadodara and supported by M/s Demasha Chemicals Pvt Ltd, Mumbai and M/s TCP Ltd, Chennai. The request was based on the grounds that the expiry of the measures would be likely to result in a continuation or recurrence of dumping and/or injury to the domestic industry. The petitioner claimed with prima facie evidence that cessation of anti dumping duty imposed on subject goods from these countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and have requested for continuation and enhancement of the anti dumping duty imposed on subject goods from subject countries for a further period of five years.

3. Having satisfied on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority initiated sunset review vide notification no. 15/1/2008-DGAD dated 19.03.08 in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- (i) After initiation of the review investigation, the Authority notified the domestic industry, all known exporters/producers in the subject countries and known importers, calling for questionnaire responses and necessary information in accordance with Rule 6(4).
- (ii) The Embassies of the subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- (iii) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from Germany and Korea RP.
 - BASF Aktiengesellschaft - Germany
 - M/s. Hansol Chemical - Korea

However none of these exporters has responded to the questionnaire in response to the above notification.

- (iv) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2006 to 30th September 2007 (18 months). However, injury analysis covered the financial years 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 and POI.

- (v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations. The requested information has been received from the DGCI&S.
- (vi) The following domestic producers of the subject goods have provided their cost and injury information for injury investigation.
- M/s Transpek-Silox Industry Ltd.
 - M/s TCP Ltd.
 - M/s Demosha Chemicals Pvt Ltd.
- (vii) A copy of initiation notification along with the importers questionnaire was also sent to the following known importers and users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4)
- | | |
|--|--|
| ➤ Malwa Industries Ltd, | ➤ Modern Denim |
| ➤ Oswal Denim | ➤ S. Kumars Ltd. |
| ➤ Ginni International, | ➤ Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. |
| ➤ The Arvind mills Ltd. | ➤ Madura Coats Limited |
| ➤ Bhiwani Textiles Mills | ➤ GSI (India) Limited (Formerly Guj. Spinners Ltd.) |
| ➤ Siris India Ltd. | ➤ Gianchand Ramji Dass |
| ➤ Mafatlal Burlington Ind. Ltd. | ➤ Raymond Denim Ltd. |
| ➤ Blue Blends India Ltd. | ➤ Reliance Textile Industries, Ltd, |
| ➤ K. G. Denim Ltd. | ➤ Birla VXL Limited |
| ➤ Sri Renuga Soft-X Towels (A 100% EOU Divsn of Shri Renuga Textiles Ltd.) | ➤ Welspun Terry Towels (A Unit of Welspun Indian Ltd.) |
| ➤ Century Denim (A Divsn of Century Textiles & Ind. Ltd.) | ➤ Raymond Limited |
| ➤ JCT Limited | ➤ Andhra Pradesh Paper Mills Ltd. |
| ➤ Soma Textiles & Industries | |
| ➤ Morarjee Brembana Ltd. | |

However none of the importers or users has filed response to the questionnaire.

- (viii) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- (ix) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

- (x) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.
- (xi) In accordance with Rule 6(6), the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 12th January 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- (xii) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (xiii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.
- (xiv) The Authority issued a detailed Disclosure Statement on 9.3.2009 for submission to the interested parties giving thereby essential facts under consideration and views expressed thereon have been duly incorporated in the present findings.
- (xv) *** in this finding represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

C.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

5. Following issues have been raised by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

(i) Since the present investigation is a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the product over the period.

(ii) The goods produced by the domestic industry are like articles to the imported product.

C.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties

6. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

7. The product under consideration in the present investigations is Sodium Hydrosulphite. The product under consideration is also known by a number of alternative names which include Hydrosulphite Concentrate or Sodium Dithionite.

8. Sodium hydrosulphite is a chemical with chemical formula $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$. It is a white or greyish white crystalline powder, free from visible foreign particles, with pungent odour. It has been imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under sub-heading 2832.10.20. Though the classifications sub-headings 2831.10.10 and 2832.10.20 suggest description as Sodium Hydrosulphite but correct Custom classification may be treated under 6 digit heading 2831.10 as Sodium Sulphites. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that the investigation covers all the forms of Sodium Hydrosulphite within the scope of the product under consideration.

9. There is no significant difference in Sodium Hydrosulphite produced by the Indian industry and Sodium Hydrosulphite exported from Germany and Korea RP, which can have an impact on price. Sodium Hydrosulphite produced by the Indian industry and imported from Germany and Korea RP are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Sodium Hydrosulphite produced by the domestic industry and imported from Germany and Korea RP are being treated as like article in accordance with the anti dumping Rules.

D. Standing and Scope of the Domestic Industry

D.1 Views of the domestic industry

10. (i) The petition was filed by M/s Transpek Silox Industry Ltd. There are four companies in India who created capacity for production of Sodium Hydrosulphite, namely M/s Transpek Silox Industry Ltd., Demosha Chemicals Pvt. Ltd., TCP Ltd. and Gulshan Chemicals Ltd. M/s. TCP Ltd, and M/s Demosha Chemicals Pvt. Ltd., have supported the petition and must be considered as "domestic industry" within the meaning of the rules.
- (ii) Production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian Production and therefore petitioner should be treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules.

D.2 Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested parties

11. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submission with regard to "domestic industry".

D.2 Examination by the authority

12. There are four producers of the subject product in India, namely M/s Transpek Silox Industry Ltd., Demosha Chemicals Pvt. Ltd., TCP Ltd. and Gulshan Chemicals Ltd. Petition for review, continuance and enhancement of anti dumping duty was filed by Transpek Silox Industry Ltd. and supported by M/s Demosha Chemicals Pvt. Ltd. and TCP Ltd.. Subsequent to initiation, TCP Ltd. and Demosha Chemicals Pvt. Ltd., have provided all relevant information with regard to injury to the domestic industry. Production by Transpek Silox Industry Ltd., Demosha Chemicals Pvt. Ltd. and TCP Ltd. command significantly higher share than 50% in Indian production.

13. Rule 2(b) under the Rules provides as follows:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case [such producers may be deemed] not to form part of domestic industry"

14. Thus, in a situation where information with regard to domestic producers as a whole is not available, the Rules require the Authority to consider those producers whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production. Therefore, having regard to the legal provisions and facts & circumstances of the present case, the Authority considers that Transpek Silox Industry Ltd., Demosha Chemicals Pvt. Ltd. and TCP Ltd. constitute domestic industry for the purpose of the present investigations within the meaning of the Rules.

E. DUMPING DETERMINATION

E.1 Views of the domestic industry

15. (i) Normal value in Germany should be determined on the basis of prices of sodium hydrosulphite prevailing in the European Communities (EC). The normal value has been claimed on the basis of actual selling price in the EC. Export price has been claimed on the basis of weighted average of the import prices. Considering the expenses incurred between CIF import price and ex-factory level, it would be seen that the Foreign Producers have continued dumping.
- (ii) Dumping from Europe is likely to continue in the event of revocation of anti dumping duties. In fact, dumping is likely to intensify in the event of revocation of anti dumping duties, given capacities far above domestic demand in Europe.

E.2 View of exporters/importers and other interested parties

16. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to normal value.

E.3 Examination by the Authority

17. Under section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:
- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic*

market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and ~~general~~ costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

GERMANY

Normal Value

18. None of the exporters from Germany has responded to the initiation notification and provided information in the form and manner prescribed. Domestic industry provided evidence of the price at which the product under consideration has been sold in the domestic market in the EU. None of the other interested parties has provided any information which can be used for determination of normal value. In the absence of information in the prescribed format, the authority made efforts to gather data from the public domain (World Trade Atlas) but no specific data was available for the subject goods. Therefore the Authority relied upon the facts available as per Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules to determine the normal value. The Authority also relied upon the information with regard to selling price in EU as provided by the domestic industry. Accordingly, the normal value at ex-factory level has been worked out as US\$ *** per MT as follows:

Price in Euro/MT	Invoice 1	Invoice 2	Average
Volume(Kg)	***	***	***
Value(Euro)	***	***	***
CIF Price(Euro/MT)	***	***	***
Local freight & Insurance (Estimated)	***	***	***
Credit cost @ 30/60 days credit	***	***	***

Prevailing price in the EC	***	***	***
Exchange Rate: Euro to US\$	***	***	***
Prevailing price in the EC in US\$	***	***	***

Export price

19. None of the exporter from Germany has responded to the initiation notification and provided information in the form and manner prescribed. Domestic industry has provided the details of the price at which goods were imported during the investigation period. None of the other interested parties has provided any other information which can be used for determination of export price. In absence of information in the prescribed format, the Authority relied upon the facts available as per Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules to determine the export price. Accordingly, the data reported by the DGCI&S for imports from Germany has been relied upon to determine weighted average import price. Since this price is at CIF level, adjustments have been made on account of ocean freight, overseas insurance, inland freight, port expenses, and bank charges to determine ex-factory export price. The ex-factory export price has been determined as at US\$ *** per MT as follows:

Particulars	Unit	Price/MT
Export Price CIF	Rs/MT	41,493
Exchange rate	1USD	44.27
Export Price CIF	USD/MT	937.27
Ocean Freight	USD/MT	***
Marine Insurance 0.5%	USD/MT	***
FOB Export Price	USD/MT	***
Inland Freight - 1%	USD/MT	***
Port Expenses - 0.5%	USD/MT	***
Bank Charges - 0.5%	USD/MT	***
Net Export Price	USD/MT	***

Dumping margin

20. Considering the normal value and export price determined as detailed above, dumping margin has been determined in respect of imports reported in India during the investigation period. The dumping margin has been determined as US\$ *** Per MT which is ***% of the export price calculated as follows:

Particulars	Unit	Price/MT
Normal Value	US\$/MT	***
Export Price	US\$/MT	***
Dumping Margin	US\$/MT	***
Dumping Margin %	%	50-60%

KOREA RP**Normal Value in Korea RP**

21. None of the exporter from Korea RP has responded to the initiation notification and provided information in the form and manner prescribed. In the absence of any response, the Authority relied upon the best available information for determination of normal value in Korea RP on the basis of construction by estimating cost of production in accordance with Rule 6(8) supra. The normal value so determined for Korea RP is US\$ *** per MT. Therefore, basing on the import prices of major raw materials (Methanol and Soda Lye) as provided by the domestic industries taking from kita.org the normal value comes to US \$ ***/Mt, which is more than the normal value determined by the authority basing on the DGCIS data of raw materials import in India. The normal value has been constructed by adopting weighted average of DGCIS import data in to India, prices of major raw materials, i.e. Sodium Formate, Methanol and Caustic Soda, best consumption factors for these raw materials and best known estimates of conversion cost during the relevant period. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin has been added to the cost of production so determined. Normal value has been calculated as follows:

	Rs per Mt
Raw material cost	***
Utilities	***
Conversion cost	***
Finance cost	***
Full cost of production	***
Reasonable profit @ 5%	***
CNV Rs per Mt	***
Exchange Rate	***
CNV US\$ per Mt	***

Export price

22. Although there is no current imports from Korea RP to India, basing on the information available in the website www.kita.org, the Authority noted that significant exports have taken place from Korea RP to a number of other countries i.e. Viet Nam, Indonesia, Bangladesh and Pakistan etc. @ US \$ *** on FOB basis. After making acceptable adjustments for inland freight, port expense and bank charges, the authority determined the ex-factory export price in respect of Korea RP with regard to third country at US\$ *** per MT as follows:

Particulars	Unit	Price/MT
FOB Export Price (Korea to World)	US\$/MT	***
Inland Freight - 1%	US\$/MT	***
Port Expenses - 0.5%	US\$/MT	***
Bank Charges - 0.50%	US\$/MT	***
Net Export Price	US\$/MT	***
Exchange rate	44.27	

Dumping margin

23. The Authority noted that none of the exporters from Korea RP has submitted response to the exporter's questionnaire. In view of that and in view of the significant exports from Korea RP to a number of countries, the Authority examined the extent of dumping in respect of these exports to third countries. Considering the estimates of normal value and the price at which goods have been exported to various countries, dumping margin in respect of exports to other countries was determined on the basis of weighted average export price to third countries for the purpose of establishing likelihood of the recurrence of dumping in the event of revocation of anti-dumping duty. It was found that dumping margin in respect of exports to third countries is USD *** per MT which is ***% of the export price. In view of the above scenario, in all likelihood, Korea RP may export the subject goods to India at the same price at which they are exporting to third countries and in the event of revocation of the anti-dumping duty it may lead to recurrence of dumping. Dumping margin in respect of Korea RP has been calculated as follows:

Particulars	Unit	Price/MT
Normal Value	US\$/MT	***
Export Price	US\$/MT	***
Dumping Margin	US\$/MT	***
Dumping Margin %	%	20-30%

E.4 Likelihood of dumping**GERMANY****Views of the domestic industry**

24 (i). The exporters have continued dumping significantly even after the imposition of anti-dumping duty. Thus, it is a situation where the

producers have been able to export significant volumes in spite of anti dumping duties (in fact, volumes have rather increased), it is evident that the volumes would only at best increase, if the present anti dumping duties are revoked. Dumping is likely to continue in significantly increased proportion in the event of revocation of anti dumping duties. There are no changes in the parameters/ circumstances prevailing at the time of original investigation and at present. Dumping has continued and dumping margin has increased, as would be seen from the table below:-

Country	Original Investigation	Present Investigation
<u>Germany</u>		50-60%
➤ BASF	22.97%	
➤ Others	35.55%	
<u>Korea</u>	98.01%	No continued exports

It is evident from the above that dumping margins are not only more than de-minimis and significant, but also the extent of dumping margin has significantly increased.

- (ii) The producers in Germany have created significantly high capacities as can be seen from the table below:

Company	Capacity (TPA)
BASF	***
BASF	***
Bruggmen	***

- (iii) The price at which material is being exported by Germany to India is also an indicator of the continuation of dumping. At the landed price (without anti dumping duty), there is significant price undercutting. Thus, with

the revocation of anti dumping duties, the Indian prices would be too attractive to the Foreign Producers to export significant volumes. In case anti dumping duty in India is revoked, these producers would shift volumes to Indian market to get better realization. Therefore, in case, duty is revoked, this would lead to continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

25. In order to examine whether the dumping of the product under consideration is likely to continue or intensify with the revocation of anti dumping duties, the Authority considered the following information/evidence:

- (i) The subject goods are continued to be imported at very low and dumped prices from Germany even after imposition of duties. There are no changes in the parameters/ circumstances prevailing at the time of original investigation and at present. In view of the same, the producers in Germany are likely to continue dumping of the product in the event of revocation of duties. This is evident from the table given below:

	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Landed price of imports				
Subject countries	41576	41684	49882	46099
Other Countries attracting Duty	36712	30329	26288	42244
Net sales realization (Rs/Mt)	***	***	***	***
Trend	100.00	92.74	99.95	104.38
Non injurious price				***,

- (ii) The domestic industries have claimed that the producers in Germany have created significantly high capacities as follows:

Company	Capacity (TPA)
BASF	***
BASF	***
Bruggmen	***

Although no corroborative evidence has been submitted by the domestic industries in support of the above claim and no information is available in the public domain to the above regard, since the exporters have not come forward to rebut the above claim, the authority holds that there are freely disposable capacities in Germany.

KOREA RP

Views of the domestic industry :

26. The following views have been submitted by the domestic industries:

- (i) Since there is no import from Korea, the Authority is required to determine likelihood of recurrence of dumping.
- (ii) Korea RP is importing significant volumes from China at very low prices. Therefore, revocation of duty would result in recurrence of dumping.
- (iii) The price at which Korea is exporting the product to third countries is materially below associated normal value, thus establishing dumping in third country exports.
- (iv) The prices at which Korea is exporting to third countries are significantly below prevailing prices in India. Therefore, in the event of revocation of duty Korean producers will be in a position to export the material at a price higher than third country, and yet, the same should be substantially lower than the prices in India.
- (v) Korean exports would be undercutting the Indian prices to a significant extent and yet Korean supplies will get a higher price than the prices being realized in third countries. This clearly establishes likelihood of dumping and injury

Examination by the Authority

27. The published data of Korea RP in www.kita.org shows significant continued imports of sodium hydrosulphite in to their country. Majority (about 99%) of these imports are from China, a country already attracting antidumping duty in India. Further, the price of export from Korea RP, which is lower than the estimated normal value, is significantly higher than the import price into Korea RP as would be seen from the table below:

	Volume (Mt)	US\$ per Mt
Constructed Normal Value		***
Import in to Korea from world	7946.08	671.78
Import in to Korea from China	7867.65	663.48
Export price of Korea		867.82

In view of the above situation, in the event of revocation/reduction of anti-dumping duty against Korea RP, in all likelihood Korea RP may restart dumping in to India. Although due to the extant anti-dumping duty against China the subject goods of Chinese origin may not find a safe passage in to India through Korea RP directly, it may result in creation of productive surplus in Korea RP which they may dump in India. Moreover, considering the selling price in India as Rs. ***/ Mt (USD ***/ Mt), the low import prices of the subject goods in Korea RP and high price/demand of the subject goods in India may become highly attractive for the Korean producers/exporters to dump subject goods in Indian market.

F. Injury and Causal Link Determination***F.1 Views of exporters, importers, users and other interested parties.***

28. No response has been received from any producer/exporter in Germany and Korea RP, or from any other interested parties.

F.2 Views of the domestic industry

29. The domestic industry has raised a number of arguments with regard to injury and causal link, which are summarized below. The main arguments are that

- (i) Performance of the domestic industry deteriorated significantly in 2004-05 and improved thereafter in 2005-06. Performance has however declined once again in the proposed investigation period.
- (ii) Parameters such as profits, capacity utilization show a deterioration over the injury period.
- (iii) Parameters such as cash profits and return on investments continued to remain negative.
- (iv) Parameters such as market share, production, sales volumes continued to remain sub-optimal.
- (v) Domestic industry could have sold more material, in the absence of dumped imports, which would have resulted in improvement in production, profitability and all related parameters.

F3. Examination by the Authority

30. The Authority has taken note of various arguments raised with regard to injury to the domestic industry. The Authority notes that the current dumping margin from the subject countries are above de minimis level. The Authority, therefore, proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

31. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases,

32. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the Anti Dumping Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

33. The Authority has taken note of the arguments on injury examination and addressed the issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties.

34. For the purpose of current injury analysis the authority has cumulatively examined the volume and prices effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any. Accordingly the volume and price effects of dumped imports have been examined as follows:

a) Assessment of Demand

35. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the product under consideration, the Authority added the sales volume of the domestic industry and other Indian producers to the total imports into India, which has been summarized as under:

Unit in MT	2003-04	2004-05	2005-06	POI Annualized
Sales of Domestic industry	23412	24015	25716	25971
Sales of Other Indian Producers	7500	7500	9022	8397
Total Imports	1518	1365	987	3888

Demand	32430	32880	35725	38256
--------	-------	-------	-------	-------

The Authority notes that the demand has shown a positive trend and grew over the injury period. The growth in demand during POI over base year was about 18%.

b) Import volumes and market share

36. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under :-

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India"

37. The Authority has examined the claim of the domestic industry as per DGCI&S data up to February 2007 and thereafter IBIS data and after comparing with transaction wise import data from DGCI&S source, it has been found that there is no significant difference. The Authority has determined the volume of imports based on only DGCI&S source.

	2003-04	2004-05	2005-06	POI Annualized
Imports (MT)				
➤ From Germany	335	156	338	1423
➤ From Korea	36	67	0	0
➤ Subject countries	371	223	338	1423
➤ Other countries attracting ADD	517	765	545	1937
➤ Other countries	630	378	103	528
➤ Total imports	1518	1366	986	3888

Market share in imports (%)				
➤ Germany	22.07	11.42	34.28	36.60
➤ Korea RP	2.37	4.91	0.00	0.00
➤ Subject countries	24.44	16.33	34.28	36.60
➤ Other countries attracting ADD	34.06	56.00	55.27	49.82
➤ Other countries	41.50	27.68	10.45	13.58
Demand (MT)	32430	32880	35725	38256
Market share in demand (%)				
➤ Germany	1.03	0.47	0.95	3.72
➤ Korea RP	0.11	0.21	0.00	0.00
➤ Subject countries	1.14	0.68	0.95	3.72
➤ Other countries attracting ADD	1.60	2.33	1.53	5.06
➤ Other countries	1.94	1.15	0.29	1.38
➤ Domestic industry	72.19	73.04	71.98	67.89
➤ Other producers	23.13	22.81	25.25	21.95
➤ Indian industry	95.32	95.85	97.23	89.84
Production of Indian industry (MT)	32288	34578	36172	35626
Dumped imports in relation to production of Indian industry (%)				
➤ Germany	1.04	0.45	0.93	4.00
➤ Korea RP	0.11	0.19	0.00	0.00
➤ Subject countries	1.15	0.64	0.93	4.00
➤ Other countries attracting ADD	1.60	2.21	1.51	5.44

The Authority concludes that

- i) The volume of dumped imports from subject countries stagnated between 2003-04 and 2005-06. The volume however increased sharply in POI.
- ii) Share of subject countries increased significantly over the injury period and particularly during POI.
- iii) The market share in demand in respect of subject imports which was only 1.14% during 2003-04 reached to level of 3.72% in POI. At the same time, share of other countries which are already attracting anti dumping duties has also increased over this period. As a result, market share of domestic industry, which was 72.19% during 2003-04 declined to 67.89% during POI.
- iv) The import from subject countries in relation to Indian production declined upto 2005-06 but went up thereafter and reached to a level of 4% during POI as compared to 1.15% during 2003-04.
- v) Even when the subject imports are attracting anti dumping duties, the imports have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption in India.

c) Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry

38. In a review investigation, it is required to examine whether there has been a significant price effect by the dumped imports as compared with the price of like product in India or wheather there is likelihood of recurrence of price effect after revocation of duty.

39. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market an analysis of import prices over the injury period has been made, as shown below:

CIF export price Rs/MT	2003-04	2004-05	2005-06	POI Annualized
Exports from subject country	32931	34392	42946	41493
Other Countries attracting Anti Dumping Duty	29079	25024	22633	38023
All Imports	28871	26206	20690	37105
Net sales realization	***	***	***	***
Trend	100.00	93.74	99.95	104.38

40. The Authority notes that the movement in the selling price of the domestic industry are in tandem with the import price in India. It is also noted that the price difference between other countries attracting anti dumping duty and subject countries was high in 2004-05 and 2005-06, thus resulting in low volume of imports from subject countries. However, with the price difference reducing in ROI, the volume of subject imports increased significantly.

d) Price undercutting

41. In order to ascertain the price undercutting being caused by the dumped imports, the Authority has compared net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization was arrived after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry. This is evident from the table given below:

	2003-04	2004-05	2005-06	POI
<i>CIF export price Rs/MT</i>				
Subject countries	32931	34392	42946	41493
Other Countries attracting Duty	29079	25024	22633	38023
<i>Customs duties</i>	25%	20%	15%	10%
<i>Landed price of imports</i>				
Subject countries	41576	41684	49882	46099
Other Countries attracting Duty	36712	30329	26288	42244
<i>Net sales realization (Rs/Mt)</i>	***	***	***	***
Indexed	100	92.74	99.95	104.38
<i>Cost of sales (Rs/Mt)</i>	***	***	***	***
Indexed	100	102.62	97.05	102.94
<i>Price undercutting price Rs/MT</i>				
Exports from subject countries	***	***	***	***
Other Countries attracting duty	***	***	***	***
<i>Price undercutting price (%)</i>				
Exports from subject countries	1-10	Negative	Negative	1-5
Other Countries attracting duty	10-20	20-30	40-50	10-15
<i>Non-Injurious price Rs/Mt</i>				***

42. It is noted that the dumped imports were undercutting the prices of the domestic industry during POI. Thus, if the present anti dumping duties are withdrawn, it is evident that the imports would significantly undercut the prices of the domestic industry in the market. It is also noted that price undercutting is quite significantly positive from other countries which are at present attracting anti dumping duties. The domestic industry requested for upward revision in these duties and the Authority is at present conducting mid term review investigations in respect of imports from these countries.

e) Price suppression/depression

43. In order to assess whether the imports from the subject countries were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry, the Authority compared the trends in selling prices and cost of production, as seen in the table above. It is noted that selling prices of the domestic industry declined very significantly in 2004-05 as compared to preceding year. Thereafter, whereas cost of production declined, selling price increased in 2005-06. However, in the POI, where the volume of imports increased very significantly from the subject sources, increase in the selling price was less than increase in the cost of production. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry whenever the volume of dumped imports was significant.

f) Economic Parameters relating to the Domestic Industry

44. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Production, sales, capacity and capacity utilization

45. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below.

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI Annualized
Capacity	Mt	31000	31000	32625	37500
Production	Mt	25169	26371	27152	27361
Domestic sales	Mt	23412	24015	25716	25971
Capacity utilization	%	81	85	83	73
Unutilized Capacity	Mt	5831	4629	5473	10139

It is noted that capacity, production and sales of the domestic industry increased but capacity utilization declined over the period. Thus, the domestic industry has been able to improve its volumes after imposition of anti dumping duties. It is however found that the subsequent increase in import volumes prevented further growth in production and sales. Consequently, capacity utilization declined and domestic industry is left with unutilized capacity of 27% during POI.

Profit, return on capital employed and cash flow

46. The profit of the domestic industry declined up to 2004-05 and improved thereafter in 2005-06 with decline in import volumes. However, profitability deteriorated once again in the POI with significant increase in the imports. This is evident from the table given below:

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Profit/(Loss) per unit	Rs/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100.00	-1,651.75	357.34	123.08
Profit/(Loss) (PBT)	Rs/Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100.00	-1,777.40	415.06	144.32
Profit/(Loss) (PBIT)	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	-683.44	327.31	232.61
Return on investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	-702.34	259.65	173.10
Cash profits	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	-1,740.11	788.99	687.02
Volume of imports					
➤ Subject countries	MT	371	223	338	1423
➤ Total imports	MT	1518	1366	986	3888

47. The domestic industry was faced with low return in 2003-04, which turned negative in 2004-05. The domestic industry could significantly improve its return on investments in 2006-07. However, with decline in profits in POI as a result of increase in imports once again, return on capital employed declined in POI. In any case, the return on investments were substantially lower than the reasonable levels.

48. All the domestic producers are multi product companies and cash flow situation of the company would not be indicative of the situations in the subject product. Hence the Authority has examined cash profits over the years and the same is as shown above. The position with regard to cash flow shows the same trend as that of profits and return on investments. The domestic industry was faced with low cash flow in 2003-04, which turned negative in 2004-05. The domestic industry could significantly improve its cash profits in 2006-07. However, with decline in profits in POI as a result of increase in imports once again, cash profits declined in POI.

Employment, wages and productivity

49. The details regarding employment, wages and productivity are given below:

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Number of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	100.19	102.46	103.60
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	99.74	103.22	116.98
Productivity	MT/person	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	104.57	105.29	105.03

The Authority notes that there was no significant changes in employment level. Wages have shown normal increases. Productivity, expressed in terms of production per employee shows some improvement.

Inventories

50. Average stock of finished products with the domestic industry showed declining trend from the table below:

	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Average stock	Mt	1733	1549	1219	1003
No. of days sales in stock	Mt	27	24	17	14

Growth

51. Large number of the injury parameters show adverse trend during the period under examination. While there was substantial improvements and positive growth in 2005-06, the same once again became negative in respect of a number of parameters, even though this was positive in respect of production, sales volumes and inventories.

H. FINAL FINDINGS:

52. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from Germany is substantial and above de-minimis.
- ii) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices and the likely dumping margins in respect of imports from Korea RP is substantial and above de-minimis.
- iii) The subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn.
- iv) *Even though the domestic industry has marginally improved its performance in terms of capacity, production and sales, its profitability deteriorated during the POI and the situation of domestic industry continues to be fragile. The dumped imports from Germany continues to cause substantial injury to the domestic industry and the likelihood of dumping from Korea RP is lurking above the heads of the domestic industries threatening to cause substantial injury in the event of revocation of the anti-dumping duty. Should the present anti dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify.*

I. Indian industry's interest and other issues

53. The Authority recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practice, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the

availability of the products to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

54. The purpose of anti dumping duties , in general ,is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the country. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way ,and ,therefore ,would not affect the availability of the products to the consumers.

J. Recommendations

55. Having concluded that the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation or resumption of dumping and injury on account of imports from Germany and Korea RP if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from the subject countries.

56. Having examined the current dumping and likelihood of dumping to be imminent in case of withdrawal of the current measure in place, the Authority recommends continued imposition of Anti-Dumping Duty in place as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/34/2002-DGAD Dated 20.10.2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, Dated 22.10.2003 and notified by the Central Government vide Notification No. 173/2003-Customs Dated. 3.12.2003.

57. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority